एशिया के ऊपर उपोव (UPOV) 1991 का खतरा

मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला किसान अपने बीजों को OFAI (Organic Farmers Association of India) द्वारा आयोजित राष्ट्रीए जैविक महोत्सव (उदयपुर) में बेचते हुए। फोटो : ग्रेन

दुनिया भर की 60 प्रतिशत आबादी और 74 प्रतिशत किसान एशिया में रहते हैं। इस वक्त यहां एक बड़ा संकट छाया हुआ है। नए कानूनों और नियमों[1] को बना कर यहां बीजों के निजीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। एशिया में इस्तेमाल होने वाले 80 प्रतिशत बीज आज भी किसानों के पास से ही आते हैं, जो अपनी पिछली फसल से छांट कर रख लेते हैं।[2] निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए इस परम्परा को गैर–कानूनी बनाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि हर फसल के पहले किसान बाजार से नए बीज खरीदे ताकि वे उससे मुनाफा कमा सकें। किसान संगठनों और जनहित समूहों के अनुसार यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिसके पास बीज होंगे वही पूरी खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करेगा।

---

[1] Jingzhong Ye and Lu Pan, "Concepts and realities of family farming in Asia and the Pacific", FAO, 2016, www.fao.org/3/a-i5530e.pdf

[2] GRAIN, 'Seed laws that criminalise farmers: resistance and fightback', April 2015, https://www.grain.org/e/5142

बीजों का निजीकरण करने के दो मुख्य तरीके हैं – (1) बीज कानून के माध्यम से – जो निर्धारित करता है कि बीजों को कैसे बेचा जाएगा; या (2) बौद्धिक संपदा कानून (IPR) – जो पौध–प्रजनकों (breeder) को एकाधिकार देता है। इन दोनों तरीकों का लक्ष्य एक ही है – स्थानीय या देसी किस्मों पर रोक लगाना, जिनमें विविधता है और जो लगातार विकसित हो रही हैं। सरकार इन बीजों को इसलिए दूर करना चाहती है क्योंकि इनसे औद्योगिक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, या सुपरमार्केट को फायदा नहीं पहुंचता, जो आज कॉर्पोरेट नियंत्रित ''प्रगति'' का मुख्य आधार बने हुए हैं।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत 1994 में स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार, करीब–करीब दुनिया के सभी देशों के ऊपर यह बाध्यता है कि वे अपने यहां के पौधों की नई किस्मों के ऊपर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नियम लागू करें। इसे पेटेंट कानून की मदद से या ऐसा ही कोई वैकल्पिक कानून बनाकर किया जा सकता है। यहां वैश्विक बीज उद्योग की पहली पसंद है – ''यूपोव' (UPOV) अर्थात् 'पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय यूनियन''। यह एक तरह की पेटेंट व्यवस्था है जिसे यूरोप में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए करीब 60 साल पहले तैयार किया गया था। यूपोव के तहत पौध–प्रजनकों (plant breeders) को 20–25 वर्षों के लिए उनके द्वारा तैयार बीजों के ऊपर एकाधिकार प्रदान किया जाता है। यह उन बीजों के ऊपर लागू होता है जो नई, विशिष्ट, समरूप और स्थिर हों। इस दौरान कोई भी बिना पौध–प्रजनक की अनुमति के इन बीजों का उत्पादन, प्रजनन, बिक्री, या विनिमय नहीं कर सकता। बीज उद्योग के लिए अपने निवेश की भरपाई करने का इससे बेहतर नियम और क्या हो सकता है। अक्सर इन्हें इस प्रकार तैयार किया जाता है कि किसान बीजों के साथ–साथ कृषि–रसायनों के जाल में भी फंस जाएं।

मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं में यूपोव को मानने का दबाव

एशियाई देशों के ऊपर अलग–अलग समझौता वार्ताओं के जरिए यूपोव में शामिल होने का या कम से कम यूपोव 1991 (क्योंकि इसे अंतिम बार 1991 में संशोधित किया गया था) के नियमों को मानने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दोनों ही तरह की वार्ताओं में हो रहा है – चाहे वो यूरोपीय संघ–भारत जैसी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं हों या क्षेत्रीय वार्ताएं, जैसे 'ट्रांस–पेसिफिक पार्टनरशिप' (TPP) या 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (RCEP)।[3]

'ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप' (TPP) 2016 में बनी थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीले, न्यूजीलैण्ड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम, जापान और मलेशिया शामिल हैं। TPP के अनुसार सदस्य देश चाहें तो WTO में दी गई छूट का इस्तेमाल करके पौधों और पशुओं को पेटेंट कानून से बाहर रख सकते हैं परंतु उन्हें यूपोव 1991 की शर्तों को मानना होगा और पौधों की नई किस्मों को पेटेंट सुरक्षा के अंतर्गत लाना होगा।[4] दुर्भाग्यवश, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया की सरकारें इसमें शामिल होने को तैयार है।

---

[3] For an overview of trade talks imposing UPOV, see GRAIN, 'Trade agreements privatising biodiversity outside the WTO: 2018 update', August 2018, https://www.grain.org/e/6030.

[4] See GRAIN, "New mega-treaty in the pipeline: what does RCEP mean for farmers' seeds in Asia?", March 2016, https://www.grain.org/e/5405

'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (RCEP) के ऊपर बातचीत अभी भी चल ही रही है। 2014 और 2015 में लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि जापान और दक्षिण कोरिया बाकी सभी सदस्य देशों के ऊपर यूपोव 1991 में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। एशिया में केवल ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम यूपोव के सदस्य हैं। इसका मतलब यह है कि भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के आठ अन्य देशों को भी यूपोव 1991 को स्वीकार करना पड़ेगा और किसानों के अधिकारों को खत्म करना पड़ेगा जिससे वे अपने से बीजों का उत्पादन, विनिमय और संचयन नहीं कर पाएंगे। किसान संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने इसका इतना जोरदार प्रतिरोध किया कि इस प्रावधान को समझौते के दस्तावेज से हटाना पड़ा।[5] और तो और भारत अब इस समझौता वार्ता से बाहर निकल चुका है।

तो यह रही व्यापार समझौता वार्ताओं की पृष्ठभूमि जहां यह तय है कि सभी देशों को यूपोव 1991 को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह विशेष रूप से उन समझौतों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें यूरोपीय सरकारें शामिल हैं – जैसे यूरोपीय संघ, ब्रेक्सिट (Brexit) के बाद का यूनाइटेड किंगडम, और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association)। हमें अंदाजा है कि जल्द ही अमेरिका के नेतृत्व में भारत और फिलीपींस के बीच नई समझौता वार्ताएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में हमारे लिए जमीनी स्थितियों को जानना और भी जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार सारे देशों के ऊपर यूपोव 1991 में शामिल होने के लिए और किसानों के बीजों को खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

चीन

छठवीं राष्ट्रीय जनगणना 2010 के अनुसार चीन की आधी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। चीन में बीज बचाने और अपने ही खेत के बीजों को दुबारा लगाने का समृद्ध इतिहास है। हालांकि कृषि में औद्योगीकरण और संकर बीजों के प्रसार के कारण धीरे–धीरे पारम्परिक बीज खत्म होते जा रहे हैं। आज चीन विश्व का सबसे बड़ा बीज बाजार बन गया है जहाँ सालाना करीब 125 लाख टन बीज बोया जाता है।

चीन के 'पौधों की नई किस्मों का संरक्षण नियमन, 1997' के अनुसार, यहां के किसान बिना किसी अधिशुल्क (royalty) का भुगतान किए अपने खेत के बीजों को रख सकते हैं व खुद के खेत में उनका दुबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसान अपने बीजों को बेच या किसी दूसरे के साथ अदला–बदली नहीं कर सकते। 2013 में थोड़े बहुत बदलावों के साथ पहली बार 'पौधों की नई किस्मों का संरक्षण नियमन' को संशोधित किया गया। 2015 में चीन के व्यापक बीज कानून में संशोधन किया गया और 2013 के 'पौधों की नई किस्मों का संरक्षण नियमन' को इसमें सम्मिलित कर लिया गया।[6]

---

[5] IPWatch, " Asian NGOs raise concern over IP and seeds in RCEP trade deal", February 2019, https://www.ip-watch.org/2019/02/26/asian-ngos-raise-concern-ip-seeds-rcep-trade-deal/

[6] Zhu Zhenyan, "Some Important Provisions in China's Revised Seed Law", TWN Info Service on Intellectual Property Issues, 4 March 2016, http://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2016/ip160302.htm

चीन 1999 में ही यूपोव का सदस्य बन गया था और 1978 के अधिवेशन की शर्तों का पालन कर रहा था। पर जब से नया बीज कानून लागू हुआ तब से चीन के ऊपर निजी बीज कंपनियों का भारी दबाव है कि वो यूपोव 1991 की शर्तों को लागू करे।[7] इसी दौरान विश्व की कई शीर्ष बीज कंपनियों का आपस में विलय हुआ। कैमचाइना (ChemChina) ने सिंजेंटा (Syngenta) को खरीद लिया, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बीज कंपनी थी। चीन के इतिहास में शायद ही कभी राज्य प्रायोजित कॉर्पोरेट रणनीति का विरोध हुआ हो, पर इस विलय का सैकड़ों लोगों ने विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों का यह मानना था कि इस विलय के बाद देश भर में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों (GMOs) को उगाया जाने लगेगा जिससे चीनी कृषि और खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा।[8]

तालिका : आवेदन की संख्या के हिसाब से यूपोव के शीर्ष 10 सदस्य

श्रेणी / रैंक	2008		2017		2018	
	सदस्य	आवेदन की संख्या	सदस्य	आवेदन की संख्या	सदस्य	आवेदन की संख्या
1	यूरोपीय संघ	3,013	चीन	4,465	चीन	5,760
2	अमेरिका	1,624	यूरोपीय संघ	3,422	यूरोपीय संघ	3,554
3	जापान	1,384	अमेरिका	1,557	अमेरिका	1,609
4	चीन	945	यूक्रेन	1,345	यूक्रेन	1,575
5	नीदरलैंड्स	751	जापान	1,019	जापान	880
6	रूस फेडरेशन	718	रूस फेडरेशन	807	नीदरलैंड्स	792
7	कोरिया गणराज्य	490	नीदरलैंड्स	763	रूस फेडरेशन	780
8	ऑस्ट्रेलिया	374	कोरिया गणराज्य	745	कोरिया गणराज्य	765
9	कनाडा	348	ऑस्ट्रेलिया	343	ऑस्ट्रेलिया	384
10	ब्राजील	207	ब्राजील	339	ब्राजील	327

www.upov.int

कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन में ज्यादा से ज्यादा किसान अपने खेत में बीजों को बचाने के बदले अब बाजार से बीज खरीदना पसंद कर रहे हैं।[9] इस वक्त चीन में 4,300 प्रमाणित बीज कंपनियां हैं, जिनमें से शीर्ष 50 कंपनियों के पास घरेलू बाजार का 35 प्रतिशत हिस्सा है। जैसे–जैसे व्यवसायिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है बीजों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं।[10] अभी तक जो किसान बीज के संरक्षित किस्मों की अदला–बदली कर कानून तोड़ रहे थे उनके ऊपर कभी–कभार ही मुकदमा होता था क्योंकि सबको पता था कि वे

[7] Yangkun Hou, "Protecting new plant varieties in China and its major problems", 7 September 2019, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-8102-7_14#:~:targetText=Based%20on%20China's%20abundant%20plant,further%20development%20of%20breeding%20work.

[8] "China citizens protest ChemChina-Syngenta deal amid GMO worries", Reuters, 8 April 2016, https://www.reuters.com/article/us-china-gmo-protests/china-citizens-protest-chemchina-syngenta-deal-amid-gmo-worries-idUSKCN0X50MA

[9] Shiyu Gu, "How to Improve the Chinese Plant Variety Protection (PVP) Legislation System During the Transition Period Towards the UPOV 1991 Act?", Master Thesis Report, Wageningen University and Research Center, 22 May2017, https://edepot.wur.nl/416375

[10] Siyuan XU, "State-driven Marketization: a preliminary review of China's seed governance and marketization history", 5th international conference of the BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies, October 2017, https://www.iss.nl/sites/corporate/files/2017-11/BICAS%20CP%205-54%20Xu%20S.pdf

जुर्माना नहीं भर सकेंगे।[11] परंतु अब इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि पौध–प्रजनकों (plant breeders) के अधिकारों के उल्लंघन को एक दंडनीय अपराध बनाया जाए। उन प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जाए जिससे अवैध रूप से बीज बेचने वाले किसानों को दण्डित किया जा सके।[12]

यूपोव का सचिवालय जिनेवा में स्थित है। यहां से हाल ही में ग्लोबल साउथ (Global South) के देशों के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया है जिसके जरिए यूपोव के फायदों का प्रचार किया जा रहा है।[13] सोशल मीडिया में यह बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के प्रमाणपत्र के लिए जो आवेदन आए हैं उनकी संख्या के आधार पर चीन का स्थान सबसे पहले नंबर पर आ गया है। पर अभी भी औद्योगिक देशों का ही ज्यादा बोलबाला है (तालिका देखें)।

बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (Belt and Road Initiative) में शामिल देशों में चीन से महंगे बीजों का निर्यात हो रहा है। इस निर्यात में हाल के वर्षों में तेजी से उभार आया है।[14] चीनी 'राष्ट्रीय बीज व्यापार संघ' (National Seed Trade Association) के अनुसार, वर्ष 2000 से 2018 तक के बीच चीन का निर्यात 13.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 69.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी गई। प्रमुख बाजारों में पाकिस्तान, कजाखस्तान और आसियान देश शामिल हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का भी हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर 'लाओलिन जीसेन (Laolin Xisen) आलू उद्योग समूह' बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव में शामिल कई देशों को आलू के बीजों का निर्यात कर रहा है। इन देशों में इजिप्ट और कजाखस्तान भी शामिल है। इसी तरह बीजिंग स्थित एटलस बीज कंपनी प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान को 110 टन बीज बेच रही है।

ऐसा लगता है कि यह बस कुछ ही समय की बात है जब चीन अधिकारिक रूप से यूपोव 1991 में शामिल हो जाएगा। इसका असर सीधे तौर पर उन देशों के ऊपर पड़ेगा जो चीन के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल हैं या बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का हिस्सा हैं। पूरी संभावना है कि उसके बाद बीजिंग भी सभी देशों को यूपोव 1991 को मानने के लिए बाध्य करेगा।

भारत

भारत ने डब्ल्यूटीओ की शर्तों का पालन करते हुए 2001 में ही बीज की नई किस्मों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया था। इस कानून की मदद से किसान किसी भी संरक्षित बीज को इस्तेमाल, अदला–बदली, संचयन या दोबारा बो सकते हैं। बस शर्त यह है कि वे उसे किसी ब्रांड के नाम से बाजार में न बेचें। यह कानून किसानों को खुद के गैर–पंजीकृत पारम्परिक बीज के उत्पादन और वितरण का भी अधिकार देता है। देश के नागर समाज

[11] A Guide to Protecting New Variety Rights in China, BUREN China Law Offices, November 2018, https://www.burenlegal.com/sites/default/files/usercontent/content-files/NVPR_online_final_compressed.pdf

[12] "China may strengthen criminal punishment to protect seed IP", 23 February 2018, http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/23/c_136994543.htm

[13] See https://twitter.com/vsgupov in particular

[14] See GRAIN, "The Belt and Road Initiative: Chinese agribusiness going global", February 2019, https://grain.org/e/6133

समूहों, विशेषज्ञों और किसान यूनियनों के लम्बे संघर्ष के बाद इस कानून में किसानों के अधिकारों के ऊपर भी एक अध्याय जोड़ा गया है। इन्हीं संघर्षों की वजह से शायद भारत अभी तक यूपोव में शामिल नहीं हुआ है।

इसी वर्ष (2019) में किसानों के अधिकारों को लेकर भारत में एक गंभीर बहस चली। पेप्सीको इंडिया कंपनी ने गुजरात के 11 किसानों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जो उनके द्वारा तैयार आलू के बीज बो रहे थे। कंपनी का आरोप था कि ये किसान बिना उनकी अनुमति के और बिना उन्हें अधिशुल्क (royalty) दिये उनके बीज से हुई पैदावार को बेच रहे थे। पेप्सीको कंपनी ने किसानों के ऊपर 28,000 से 140,000 अमेरिकी डॉलर के बीच जुर्माना लगाने की मांग की थी। इसका काफी जोरदार विरोध हुआ और अंततः पेप्सीको कंपनी को यह मुकदमा वापस लेना पड़ा।

कानूनी लड़ाई के दौरान नागरिक समाज समूहों ने पाया कि सरकार कानून के कुछ प्रावधानों को यूपोव 1991 के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही है। कुछ महीनों के बाद बीज विधेयक (Seed Bill), 2019 का प्रारूप सामने आया।[15] इस प्रारूप के अध्ययन से पता चला कि भारत सरकार के ऊपर यूपोव में शामिल होने का बड़ा दबाव है। कोई शक नहीं कि देश में तेजी से विकसित हो रहे बीज बाजार को हथियाने की यह साजिश है, जिसकी कीमत 2018 में 410 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी।

चीन की ही तरह भारतीय बीज उद्योग भी काफी महत्वाकांक्षी है। ये दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया में अपने पैर पसारना चाहते हैं। भारत का राष्ट्रीय बीज संघ (National Seed Association of India) ने हाल ही में कहा – ''मोदी सरकार को आगे बढ़कर एक वैश्विक व्यवस्था का गठन करना चाहिए जिससे हमारे पौध–प्रजनकों के व्यवसायिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके।''

अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भारत की फिर से द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं शुरू हो रही हैं। देश के किसान संगठन और नागर समाज सर्तक हैं और उन्हें पता है कि ये दोनों ही देश अक्सर अपने व्यापार साझेदार के ऊपर यूपोव का सदस्य बनने के लिए बाध्य करते हैं।

इंडोनेशिया

अन्य एशियाई देशों की ही तरह इंडोनेशिया के ऊपर भी यूपोव में शामिल होने के लिए बड़ा दबाव है। यह दबाव द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के साथ–साथ पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के ऊपर बने दो क्षेत्रीय फोरम से आ रहा है, जिसमें इंडोनेशिया की सरकार शामिल है।[16] (बॉक्स देखें)

इंडोनेशिया ने दिसंबर 2018 में EFTA (आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीट्जरलैंड और लिचेंस्टीन) के साथ एक व्यापार समझौता किया। इस समझौते में ये शामिल है कि जो भी देश यूपोव 1978 के पहले से ही सदस्य नहीं हैं, उन्हें

[15] Government of India, Department of Agriculture, "Draft Seed Bill for public comment", 2019, http://agricoop.nic.in/recentinitiatives/draft-seeds-bill-public-comments

[16] Personal communication with Dr. Efrizal Jamal, head of Indonesia plant variety protection body, July 2019.

यूपोव 1991 के प्रावधानों को स्वीकार करना होगा।[17] इस समझौते में हस्ताक्षर करने के साथ ही इंडोनेशिया की यूपोव 1991 में शामिल होने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रीय कानून को यूपोव 1991 के अनुरूप ढालने को लेकर अभी तक ज्यादा प्रगति तो नहीं हुई है परंतु फिर भी बीज के इस्तेमाल और प्रजनन की आजादी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है।

बॉक्स 1: पौधों की नई किस्मों के संरक्षण को लेकर पूर्वी एशिया फोरम और 'ई.यू. आई.पी. कीय' (EU IP Key) दक्षिण–पूर्व एशिया

जापान की पहल पर 2007 में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण को लेकर एक पूर्वी–एशियाई फोरम का गठन किया गया।[18] इसके सदस्यों में 10 आसियान देश के साथ–साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। इसका सचिवालय जापान के पास है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य सारे सदस्य देशों को यूपोव में शामिल करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने यहां पौधों की नई किस्मों का संरक्षण कानून को यूपोव के अनुरूप ढाल सकें। फोरम की गतिविधियों में प्रशिक्षण और आदान–प्रदान मुख्य हैं। फोरम द्वारा बीजों की विशिष्टता, समरूपता और स्थिरता की जांच से संबंधित नियमन और प्रक्रियाओं जैसे विषयों के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी दिया जाता है।

'आई.पी. कीय दक्षिण–पूर्व एशिया (IP Key Southeast Asia)' की शुरुआत अप्रैल 2018 में यूरोपीय संघ द्वारा एक प्रोजेक्ट के रूप में की गई। यूरोपीय कमीशन के व्यापार विभाग की पहल पर यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा कार्यालय ने इसे कार्यान्वित किया।[19] इस प्रोजेक्ट में यूरोपीय संघ को आसियान देशों के साथ व्यापार और बौद्धिक संपदा के ऊपर बातचीत करने के लिए करीब 60 लाख यूरो (करीब 48 करोड़ रुपये) देने का बजट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार कानून की सुरक्षा और क्रियान्वयन के यूरोपीय मानकों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यूरोपीय अन्वेषकों और अधिकार धारकों (जो इस मामले में निजी बीज प्रजनक हैं) के हितों को सुरक्षित रखना है, ताकि वे दक्षिण–पूर्व एशिया में व्यापार और निवेश सहजता से कर सकें।

यूरोपीय संघ हो या जापान, दोनों के ही फोरम से हम देख सकते हैं कि एशिया के कई देशों के लिए यूपोव का सदस्य बनना या किसानों के बीज अधिकार के खिलाफ कठोर कानून बनाना न ही घरेलू मांग है और न ही प्राथमिकता। यह बाहर से थोपा जा रहा है और देखा जाए तो यह दबाव भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों की तरफ से आ रहा है, जहां ज्यादातर विशालकाय बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां स्थित हैं। अब आप ही बताइये इससे किसको फायदा पहुंचने वाला है?

---

[17] EFTA, "Annex XVII referred to in article 5 protection of intellectual property", 2018, https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-annex17-intellectual-property-rights.pdf

[18] EAPVP Forum, "Introduction to the East Asia Plant Variety Protection Forum" http://eapvp.org/about/

[19] EU IP key Southeast Asia, https://ipkey.eu/en/south-east-asia

किसानों को इस बात की भी चिंता है कि यूपोव बीजों के जरिए खेती में एकरूपता (homogeneity) को प्रोत्साहित करता है। इससे आनुवंशिक क्षरण (genetic erosion) का जोखिम बढ़ जाएगा। EFTA में शामिल देशों में तुलना की जाए तो इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा विविध फसलें एवं खेती व्यवस्था है। किसानों को चिंता है कि यूपोव 1991 के बाद किसानों का अपराधीकरण बढ़ेगा। वे अपने बीजों का प्रजनन और अदला–बदली नहीं कर पाएंगे। यूपोव नहीं होने पर भी इंडोनेशिया के किसानों को अपने बीजों के प्रजनन और वितरण के लिए बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ रही है।

इंडोनेशिया में 2003 से 2010 के बीच बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों ने कम से कम 14 किसानों के ऊपर बौद्धिक संपदा कानून के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।[20] थाईलैंड की 'चरोइन पोकफंड' (Charoen Pokphand) की एक सहायक कंपनी, 'पी.टी. बीसी' (PT BISI) के मामले में तो किसानों की गिरफ्तारी भी हुई थी। कंपनी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई फिर भी कई किसानों को महीनों तक जेल में रहना पड़ा। अदालत में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील भी नहीं था। अधिकांश किसान तो यह समझ ही नहीं पाए कि उन्हें क्यों उस काम के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जिसे वे सदियों से करते आ रहे हैं।

इन मुकदमों के बाद किसानों, नागरिक समाज समूहों और वकीलों ने अपना एक गठबंधन बनाया और सितंबर 2012 में वे इस मामले को संवैधानिक अदालत में ले गए। उनका तर्क यह था कि इंडोनेशिया में पौधों की खेती का कानून छोटे किसानों और किसान प्रजनकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। उनके साथ बड़े व्यावसायिक इकाइयों जैसा व्यवहार हो रहा है, जो गलत है। संवैधानिक अदालत ने भी माना कि इस कानून के 3 अनुच्छेद वाकई में गैर–संवैधानिक हैं। इस आदेश के बाद किसानों को अपने बीज के उत्पादन, संरक्षण या वितरण के लिए अब सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।[21]

एक दूसरे मामले में मुनीरवन नाम के एक किसान को उत्तर असेह (North Aceh) में जुलाई 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर आरोप था कि जो बीज उसे परीक्षण के लिए स्थानीय सरकार से मिले थे उनका उसने व्यावसायिक लाभ के लिए वितरण किया था। जबकि सच्चाई यह है कि उन बीजों से उसकी बहुत अच्छी पैदावार हुई और उसने कुछ बीजों को अगले साल के लिए बचा कर रखा और बाकी अनाज को बेच दिया।[22] हर कोई यही करता। बड़ी मात्रा में आम जनता ने मुनिरवन का समर्थन किया और अंततः मुनीरवन के खिलाफ मुकदमा वापस लेना पड़ा।

विडम्बना की बात तो यह है कि 2013 में संवैधानिक अदालत के निर्णय के बावजूद और मुनीरवन के मामले में आम दबाव होने के बावजूद, सितंबर 2019 में कई विवादास्पद प्रावधानों के साथ एक नया पौधों की खेती कानून बनाया गया। इस कानून में यह साफ कहा गया है कि जो किसान खेती के लिए आनुवंशिक संसाधनों को इकट्ठा

---

[20] Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, "Our seed, our sovereignty - seed law victory in Indonesia", 2013, https://www.grain.org/en/article/4774-our-seed-our-sovereignty-seed-law-victory-in-indonesia

[21] Ibid.

[22] Gisela Swaragita, "Farmer arrested for producing, selling unreleased rice seed variety", 2019, https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/27/farmer-arrested-for-producing-selling-unreleased-rice-seed-variety.html

कर रहे हैं उन्हें स्थानीय और केंद्रीय सरकार को सूचित करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसानों द्वारा तैयार पौधों की नई किस्मों को वह अपने 'समूह' के अंदर ही बांट सकते हैं। अब 'समूह' की परिभाषा क्या होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। इस कानून में गैर–प्रमाणित बीजों का वितरण करने वालों के लिए अपराधिक दंड का प्रावधान भी है – उन्हें 4 से 6 साल तक की कैद हो सकती है।

कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंडोनेशिया में किसानों को लग रहा है कि बीजों के ऊपर उनके अधिकार धीरे–धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं।

मलेशिया

अभी तक तो मलेशिया की सरकार ने यूपोव को रोक कर रखा है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के आधार पर 2004 में मलेशिया ने पौधों की नई किस्म के संरक्षण के लिए एक नया कानून बनाया था, जिसमें किसानों को उनके बीजों को बचाने और पुनः इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था।

पर 2012 में मलेशिया सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2004 के कानून को यूपोव 1991 के अनुरूप बनाने के लिए उसमें संशोधन किया जाएगा।[23] इस निर्णय का नागरिक समाज संगठनों, किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण समूहों द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि यूपोव व्यवस्था को मानने के लिए किसानों को उनके अधिकार से वंचित करना पड़ेगा जिससे वे अपनी खुद की पैदावार को मुफ्त में बांट या बेच नहीं पाएंगे। इससे एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलेगा और जैव–चोरी (bio-piracy) बढ़ेगी। स्थानीय पारम्परिक ज्ञान के साथ–साथ मलेशिया की जैव–विविधता भी नष्ट हो जाएगी।[24]

एक अलग बयान में इन समूहों ने आगे बताया की मलेशिया में किसानों की औसत जोत केवल 1.32 हेक्टेयर है। इतनी बड़ी संख्या में छोटे किसानों के लिए बीज का मुख्य स्रोत अक्सर स्थानीय बाजार, खेतों से बचाए हुए बीज, रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं। इस परम्परा पर रोक लगाने से काफी नुकसान होगा और मलेशिया में किसानों की बीज व्यवस्था तहस–नहस हो जाएगी।[25]

हालांकि मौजूदा सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह 'ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप' (TPP) को बहाल करेगी या नहीं परंतु किसानों के अधिकार को ताक पर रखकर यूपोव में शामिल होने के लिए इस सरकार के ऊपर जोरदार दबाव बना हुआ है।

---

[23] Department of Agriculture Malaysia, 'New developments on PVP in Malaysia', October 2012, https://www.yumpu.com/en/document/read/37894525/pvp-in-malaysiapdf-the-east-asia-plant-variety-protection-forum

[24] Zanariah Abd Mutalib, '21 NGO bantah Malaysia sertai Konvensyen UPOV 1991', September 2019, https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/09/610836/21-ngo-bantah-malaysia-sertai-konvensyen-upov-1991

[25] 'Malaysia civil society and farmer groups' memorandum on RCEP and plant variety protection', February 2019, https://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2019/02/Malaysia-Memo-of-CSOs-And-Farmers-Groups-No-UPOV-In-RCEP.pdf

फिलीपींस

फिलीपींस में आमतौर पर किसान बीज प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहां कानूनन तौर पर संरक्षित बीजों की व्यवस्था नहीं है। केवल धान एवं मक्का के ही सुरक्षित बीज उपलब्ध हैं।[26] यहां तक कि जो किसान मक्का और धान उगाते हैं वे भी अपने बीजों को अनौपचारिक माध्यम से ही प्राप्त करते हैं – जैसे रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी से या पिछली पैदावार से। खेती के खर्च को कम करने के अलावा किसानों के बीच बीजों की अदला–बदली से पौध सामग्री (planting material) में नई जान आ जाती है। अलग–अलग किस्मों के बीजों की अदला–बदली से कीट और बीमारियां भी कम होती हैं।[27] फिलीपींस एक ऐसा देश में जहां मौसम की चरम घटनाएं घटती रहती हैं। इससे कीट और बीमारियों के आक्रमण की तीव्रता भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में किसानों द्वारा प्रजनन की गई किस्मों का अलग ही महत्व है। उदाहरण के लिए, किसानों के नेतृत्व में 'मासीपाग' (MASIPAG) कार्यक्रम चलाया गया जिसने किसानों द्वारा तैयार करीब 2,000 धान की किस्मों को इकट्ठा किया है। इनमें से 18 किस्में सूखा–सहिष्णु, 12 बाढ़–सहिष्णु, 20 खारा पानी–सहिष्णु, तथा 24 किस्में कीट और रोग सहिष्णु हैं।[28]

डब्ल्यूटीओ का पालन करते हुए फिलीपींस ने 2002 में पौधों की नई किस्मों का संरक्षण कानून बनाया था। यह काफी हद तक यूपोव 1991 के ऊपर आधारित था पर इसमें छोटे किसानों के लिए विशेष रियायतें दी गई थीं। अब सरकार नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अपने "बीज उद्योग विकास अधिनियम (Seed Industry Development Act), 1992" में संशोधन करना चाह रही है। इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का बीच भी शामिल हैं।[29] इससे पता चलता है कि खेतों से बचाए हुए बीजों का विनिमय और आपस में अदला–बदली की परम्परा यहां के किसानों में बहुत सामान्य है, इसमें ट्रांसजेनिक बीजों की अदला–बदली भी शामिल है। मोनसेंटो के राउंडअप रेडी (RoundupReady) मक्का के मामले में अनौपचारिक माध्यम से प्राप्त बीजों की कीमत औपचारिक रूप से खरीदे गए बीजों की तुलना में 10 गुना कम है।[30]

फिलीपींस सरकार ने यूपोव से कहा है कि वह 1991 कन्वेंशन के आधार पर उनके कानून का मूल्यांकन करे। पर अभी तक इसमें आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है।[31] दूसरी तरफ कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि

---

[26] Public Eye, "Owning seed, accessing food - A human rights impact assessment of UPOV 1991 based on case studies in Kenya, Peru and the Philippines", 2014, https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf

[27] Ibid.

[28] MASIPAG, 'Amidst crisis farmer scientist group launch climate resilient rice varieties', 2019, http://masipag.org/2019/09/amidst-crisis-farmer-scientist-group-launch-climate-resilient-rice-varieties/

[29] Jasper Arcalas, 'Flaw in law threatens to slow seeds sector's success', Business Mirror, June 2018, https://businessmirror.com.ph/2018/06/06/flaw-in-law-threatens-to-slow-seeds-sectors-success/

[30] Public Eye, "Owning seed, accessing food - A human rights impact assessment of UPOV 1991 based on case studies in Kenya, Peru and the Philippines", 2014, https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf#page=1&zoom=auto,-158,449

[31] Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementrian Pertanian Indonesia, 'Perkembangan negara anggota EAPVP' 2018, http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms/wp-content/uploads/2018/01/Perkembangan-Negara-Anggota-EAPVP-Forum-Indirawati-Sintya-D-SS-MA.pdf

अगर यूपोव 1991 को फिलीपींस में लागू किया गया तो किसान बीजों से जुड़ा अपना ज्ञान खो बैठेंगे और जलवायु संकट से निपटने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी।[32]

थाईलैंड

थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ का पालन करते हुए 1999 में पौधों की नई किस्मों का संरक्षण कानून बनाया था। यह कानून यूपोव की तर्ज पर ही था, परंतु इसमें किसानों को काफी स्वतंत्रता दी गई थी। किसान संरक्षित बीजों को बचा कर रख सकते थे और उसे अपने खेत में दोबारा लगा सकते थे। पर इन्हें अदला–बदली या बिक्री की अनुमति नहीं थी। कुछ विशेष फसलों के मामले में दोबारा रोपाई के लिए बीजों की मात्रा को सीमित किया गया था। इस कानून में यह भी प्रावधान था कि पौध प्रजनन से हुई कमाई का एक हिस्सा किसान ''पौधों की नई किस्मों का संरक्षण फंड'' में जमा करेंगे।[33] कहा जाता है कि इस कानून की मदद से थाईलैंड स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी, 'चरोइन पोकफंड' (Charoen Pokphand) की अंतरराष्ट्रीय बाजार में पकड़ मजबूत हो गई और यह वैश्विक बीज कॉरपोरेटों – जैसे मोनसेंटो, कारगिल और पायनियर की टक्कर की आ गई। विशेष रूप से मक्का बीज के मामले में, पर अन्य वार्षिक फसलों में भी इसका बाजार पर पूरा नियंत्रण है।[34]

लगातार बढ़ते जा रहे कॉर्पोरेट नियंत्रण के बावजूद, कई किसान और किसान संगठन अपने और अपने समूहों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले धान और मक्का के बीज का उत्पादन कर पा रहे थे। कुछ किसानों ने तो सामुदायिक बीच उद्यम की भी शुरुआत की। 'वैकल्पिक कृषि नेटवर्क' (Alternative Agriculture Network) ने 2011 में 'फ्रीडम सीड्स' (Freedom Seeds) के नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की। सालाना करीब 100 टन चमेली और पारंपरिक धान के बीजों का उत्पादन कर पाने में ये सफल रहे।[35] प्रत्येक वर्ष धान के मौसम के पहले 'फ्रीडम सीड्स' आंदोलन बीज विनिमय कार्यक्रम का आयोजन करता है, जहां आकर किसान बीजों को खरीद, बेच या अदला–बदली कर सकें। एक और सामुदायिक बीज उद्यम है – 'प्राव फार्मर सीड्स इंटरप्राइज़ेज' (Praaw Farmers Seeds Enterprises)। इसकी शुरुआत करीब 20 वर्ष पहले चियांग माई (Chiang Mai) नामक एक किसान ने की थी। इस उद्यम में उच्च पैदावार वाले शंकर मक्का बीजों का उत्पादन होता है। इसके पास मक्का बीज के कुल बाजार का 10 प्रतिशत हिस्सा है।[36] ऐसे बीज उद्यमों ने यह दिखा दिया है कि समुदाय अपने किसानों के हुनर से काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीज उत्पादन आजीविका का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

---

[32] CIDSE, "Resilient communities: The story of Masipag", November 2016, https://www.cidse.org/2016/11/18/resilient-communities-the-story-of-masipag/

[33] USDA FAS. "Thai Plant Variety Protection Act Amendment Update", November 2017, https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Thai%20Plant%20Variety%20Protection%20Act%20Amendment%20Update_Bangkok_Thailand_11-2-2017.pdf

[34] Kingkorn Narintarakul, "Thailand's freedom seeds network: Can Jack face the giant?", Mekong Commons, 2015, http://www.mekongcommons.org/thailands-freedom-seeds-network-can-jack-face-giant/

[35] Ibid. and personal communication with Alternative Agriculture Network

[36] Ibid.

2017 में थाईलैंड के कृषि विभाग ने चुपचाप 1999 के कानून को यूपोव 1991 के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा। चुपचाप इसलिए क्योंकि इसके पहले के सारे प्रयास मजबूत विरोध के कारण असफल हो चुके थे। 'बायोथाई' (BioThai) और ''वैकल्पिक कृषि नेटवर्क' (Alternative Agriculture Network) के अनुसार इस प्रस्तावित विधेयक से किसानों के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे बीज कंपनियों का बाजार के ऊपर एकाधिकार नियंत्रण भी बढ़ेगा। इस विधेयक में नई किस्मों के संरक्षण की अवधि को मौजूदा 12–17 वर्ष से बढ़ाकर 20–25 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसमें उस अनुच्छेद को भी खत्म करने की सिफारिश है जिसके तहत किसानों को अपने खेत में संरक्षित बीजों को बोने की अनुमति है। अब किसी भी उल्लंघन के मामले में अपराधिक दंड का प्रावधान है।[37] प्रस्तावित संशोधन के अनुसार कोई नया बीज अगर थाईलैंड की सामग्री पर आधारित नहीं है तो उसकी कमाई का हिस्सा जमा करने जरूरत नहीं है।[38]

अभी तक इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिली है। अभी भी इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि कैसे यह किसानों के लिए नुकसानदायक है और इससे एकाधिकृत बीज बाजार को बढ़ावा मिलेगा।[39]

वियतनाम

वियतनाम 2006 में ही यूपोव में शामिल हो गया था। एशिया में यूपोव जो हासिल करना चाहता है, वियतनाम उसका एक आदर्श नमूना है। यह अक्सर थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों को यूपोव के अनुरूप अपने कानूनों को ढ़ालने के लिए वार्ताओं का भी आयोजन करता रहता है।

यूपोव में शामिल होने से पहले वियतनाम में सारा बीज प्रजनन का कार्य (लगभग 100 प्रतिशत) निजी क्षेत्र के हाथों में था। पर 10 सालों में ही वियतनाम का बीज उद्योग पूरी तरह से सिमट गया और देश का 80 प्रतिशत बाजार केवल 8 कंपनियों के कब्जे में आ गया। इनमें से अधिकांश वैश्विक बीज कंपनियां हैं – जैसे सिंजेंटा, मोनसेंटो और जापान की साकाटा।[40] परिणाम स्वरूप, अब छोटे किसानों को अपने बीजों के उत्पादन और वितरण में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

वियतनाम में आधा से ज्यादा धान उत्पादन मेकॉन्ग डेल्टा (Mekong Delta) क्षेत्र में होता है। यहां ज्यादातर बीज प्रजनन छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। यहां के किसानों ने आपस में बीज के उत्पादन और वितरण के लिए खुद को 'बीज क्लब' (Seed Clubs) के रूप में संगठित कर रखा है। 2008 में इस क्षेत्र में करीब 300 बीज क्लब मौजूद थे। इनसे करीब 16 प्रतिशत स्थानीय धान के बीजों की सप्लाई होती थी (औपचारिक माध्यम से केवल 3.5

---

[37] Biothai, "Will collecting seeds for replanting be made a crime?", October 2017, https://www.biothai.org/node/1428

[38] USDA FAS. "Thai Plant Variety Protection Act Amendment Update", November 2017, https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Thai%20Plant%20Variety%20Protection%20Act%20Amendment%20Update_Bangkok_Thailand_11-2-2017.pdf

[39] The Nation, "Amended plant protection act 'must take care of farmers'", July 2019, https://www.nationthailand.com/news/30372158

[40] Mordor Intelligence, "Seed sector analysis – Vietnam industry, growth, trends, and forecast (2019 — 2024)", 2018, https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/seed-sector-analysis-vietnam-industry

प्रतिशत बीज प्राप्त हो रहा था)। किसानों द्वारा विकसित किए गए नई धान की किस्मों के बीज ज्यादा विविध और सस्ते होते हैं और उनसे घरेलू आमदनी और उद्यमिता को मदद मिलती है।[41] वियतनाम में बीज अध्यादेश, 2004 के अनुसार, जो किसान प्रमुख फसल का उत्पादन करते हैं उन्हें अपने बीजों को बेचने या वितरण के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पर उन्हें बीज की गुणवत्ता की गारंटी देनी होगी। इसीलिए आमतौर पर किसानों को अपने बीजों के प्रजनन और वितरण की अनुमति है, जब तक की बीजों की गुणवत्ता पर कोई सवाल न उठे।[42]

एक वियतनामी एनजीओ, 'सेंडी' (CENDI) के अनुसार लगातार कठिन होते नियम और यूपोव का आदर्श देश होने के बावजूद, आदिवासी किसान, विशेष रूप से पहाड़ों में रहने वाले अभी भी खेती के पारम्परिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास तराई के किसानों की तुलना में आपस में बीजों को बांटने, बचाने और इस्तेमाल करने की ज्यादा स्वतंत्रता है। तराई के किसान औद्योगिक खेती और कानून की पकड़ में आसानी से आ जाते हैं।

निष्कर्ष

इन सभी देशों के अनुभव से पता चलता है कि यूपोव के तहत जिस प्रकार के सामाजिक–आर्थिक फायदों को गिनाया जा रहा है, वास्तविकता में सब कुछ उसके विपरीत है। यह न सिर्फ बीज के ऊपर किसानों की स्वतंत्रता के साथ समझौता है बल्कि यह बीज उद्योग को और शक्तिशाली बनाने की साजिश है। किसानों के बीज और अनौपचारिक बीज वितरण अभी भी एशिया में एक सामान्य परंपरा है। यूपोव 1991 छोटे किसानों के लिए विनाशकारी होगा। इससे किसानों के रोजमर्रा के कार्यों – जैसे बीजों का वितरण, प्रजनन या संरक्षण की वजह से, जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, उन्हें अपराधी बना दिया जाएगा।

किसानों के बीजों का निजीकरण और औद्योगिक बीज कॉरपोरेशन के एकाधिकार को रोकने के लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत है। मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं के कारण धीरे–धीरे यह मुश्किल होता जा रहा है। इन वार्ताओं में कठोर बौद्धिक संपदा नियमों को स्थापित करने के लिए नीतिगत बदलाव लाने पर लगातार जोर डाला जा रहा है। यूपोव की मंशा साफ है – यह किसानों के बीजों को व्यावसायिक बीजों से बदलना चाहता है।

यह बेहद महत्वपूर्ण है कि मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं का विरोध किया जाए जो एशियाई देशों को यूपोव में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार के खिलाफ प्रतिरोध लगातार बढ़ रहे हैं। एशिया में व्यापार समझौता वार्ताओं के खिलाफ हो रहे संघर्षों में काफी कुछ सीखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि निजीकरण को रोकने और अपने बीजों और संस्कृति के ऊपर दुबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए किसान आंदोलन, आदिवासी समुदाय और खाद्य अधिकार कार्यकर्ताओं को अन्य क्षेत्रों में हो रहे संघर्षों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा।

---

[41] Huynh Quang Tin, Nguyen Hong Cuc, Tran Thanh Be, Normita Ignacio & Trygve Berg, "Impacts of seed clubs in ensuring local seed systems in the Mekong Delta, Vietnam", 2011, Journal of Sustainable Agriculture.

[42] Bert Visser, The impact of national seed laws on the functioning of small-scale seed system. A Country Case Study, May 2017, Oxfam Novib, https://www.sdhsprogram.org/assets/wbb-publications/770/Seedlawstudy_Bert%20Visser.pdf